

विभाग की पहल से आसान हुई उपखनिज उपलब्धता, बढ़े रोजगार के अवसर

प्रकाश जोशी • जागरण

तालुकुआं: सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन विभाग ने इस वर्ष समय पर नदियों को चुगान के लिए खोलने, पर्यावरण संरक्षण के अनुरूप उपखनिज उपलब्ध करने और रोजगार सृजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

विभाग द्वारा गौला, शारदा, नंघौर समेत विभिन्न नदियों का समय रहते सर्वे कर उपखनिज निकासी का लक्ष्य बढ़ाया गया, जिससे कारोबार प्रभावित नहीं हुआ और कारोबारियों को आंदोलन की राह नहीं पकड़नी पड़ी। पूर्व वर्षों में नदियों के देर से खुलने

और लक्ष्य समय पर नहीं बढ़ने से खनन कारोबार प्रभावित होता था, लेकिन इस बार विभाग की सक्रियता से पूरे सीजन में चुगान कार्य सुचारु रूप से चलता रहा। विभाग का कहना है कि वैज्ञानिक पद्धति से खनन होने के कारण नदियों के किनारों पर भू-कटाव में भी कमी आई है।

खनन गतिविधियां प्रदेश में रोजगार का बड़ा माध्यम भी बनी हैं। विभाग के अनुसार परिवहन, स्टोन क्रेशर, बहन संचालन, मशीन संचालन और श्रमिक कार्यों समेत अन्य गतिविधियों से लगभग सात लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है।

पांच वर्षों में 3859.79 करोड़ का राजस्व अर्जित

तालुकुआं: खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कुल 3859.79 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में 950 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष 1126.54 करोड़ रुपये का रिकार्ड राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वर्ष 2024-25 में 1040.57 करोड़ रुपये की आय हुई थी।



सरकार ने खनन नीति का सरलीकरण करते हुए पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया को ई-नीलामी के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। सरकार की मंशा है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक विधि से खनन कार्य संचालित हो, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के साथ निर्माण सामग्री भी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके। -**पुष्कर सिंह धामी**

दस हजार से ज्यादा प्रकरण दर्ज

विभाग ने पिछले पांच वर्षों में अर्ध खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए कुल 10,605 प्रकरण दर्ज किए। इन कार्रवाई में लगभग 195.50 करोड़ रुपये की वसूली की गई। विभाग का दावा है कि चेंकिंग और तकनीकी निगरानी से अर्ध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया।

शइस बार 15 सौ करोड़ रुपये का लक्ष्य मिला है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही अर्ध खनन पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए विभाग गंभीरता से कार्य कर रहा है। -**राजपाल लेवा, निदेशक, खनन विभाग**